उत्तर-पूर्व दिल्ली के हमारे ही शहर के, हमारे साथी नागरिकों को इस वक़्त खाने, पनाह, कपड़ों, दवाओं आदि की बेहद ज़रूरत है। कुछ एनजीओ और कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर जितना हो सकता है उतनी मदद पहुँचा रहे हैं। लेकिन कहाँ है दिल्ली सरकार? ये सरकार की नागरिकों के प्रति ज़िम्मेदारी है कि वे बड़े पैमाने पर ज़रूरतमंदों को सहायता पहुँचाए - और ये नागरिक संगठनों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें शामिल है:

- ऐसे शरणार्थी शिविर लगाना जहाँ बड़ी संख्या में लोग रह सकें, जहाँ खाना, पीने का साफ़ पानी, निकासी, कपड़ों का पर्याप्त प्रबंध हो
- चौबीसों घंटे खुलने वाले स्वास्थ केंद्र, और महिलाओं तथा बच्चों के लिए सुरक्षित निजी जगहें मुहैया कराना
- मानववादी एजेंसियों द्वारा तय की गई किट, जिनमें कुछ जोड़ी कपड़े और अंदरूनी कपड़े, टॉयलेट्रीज़, सेनेटरी नैपकिन, मिल्क पाउडर और अन्य ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए

दिल्ली सरकार ने वादा किया है कि वो मुआवज़ा देगी और दस्तावेज़ों में मदद करेगी। लेकिन इससे पीड़ितों का दुःख कम करने वाली फ़ौरी और मूलभूत सहायता नहीं मिलती। खाना, पनाह और स्वास्थ संबंधी मदद के अलावा, उत्तर-पूर्व दिल्ली के हमारे भाईयों और बहनों को भावनात्मक, आर्थिक और क़ानूनी सहारे की भी ज़रूरत है। हम दिल्ली सरकार से अपील करते हैं कि वे सुनिश्चित करे

- क़ानूनी सहायता केंद्र बनाना जहाँ प्रशिक्षित वक़ील हों, जहाँ क़ानून के विद्यार्थी भी हों जो गुमशिदगी रिपोर्ट दायर करने के साथ-साथ हर हिंसक घटना के मामले में एफ़आईआर भी करवाएँ
- आधार, वोटर पहचान पत्र और अन्य औपचारिक गुम हुए कागज़ात को बिना शुल्क फिर से बनवाना
- जो छात्र इस बार परीक्षाओं में नहीं बैठ पाए उनके लिए सीबीएसई दोबारा परीक्षाएँ करवाए

हम हाल ही में निर्वाचित दिल्ली सरकार से आह्वान करते हैं कि वो ये सब करे। लोगों की सेवा करने के उनके वादे को पूरा करने के लिए - खासतौर से उन लोगों की जो आज अपने ही शहर में डरे हुए हैं और जिन्हें सहायता की ज़रूरत है।